ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, *RNI:UPBIL04292,REG.No.:561/2013-14, Vol.-I, No.-1,* **PP-134-135**, *YEAR 2014*

वैश्वीकरण का भारतीय उद्योगों पर प्रभाव

❑ डॉ0 अंगद प्रसाद गुप्ता*

वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ 'एकीकृत' करना। भारतीय सन्दर्भ में इसका अर्थ है विदेशी कंपनियों को भारत की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में निवेश करने की अनुमति देकर अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिये खोलना, विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम जैसे कानूनों को धीरे–धीरे समाप्त करके बहुराष्ट्रीय निगमों को देश में आने की व निवेश करने की सुविधाये प्रदान करना, भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग करने की अनुमति देना तथा दूसरे देशों में संयुक्त परियोजनाएं चालू करने के लिये प्रोत्साहित करना मात्रात्मक प्रतिबंधों के स्थान पर धीरे–धीरे प्रशुल्कों को प्रतिस्थापित करन और फिर धीरे –धीरे उनकों भी कम कर देना जिससे आयात् उदारीकरण कार्यक्रमों को व्यापक आधार पर लागू किया जा सके तथा कई तरह के निर्यात् प्रोत्साहनों (जैसे नकद मुआवजा, सहायता, शुल्क वापसी की व्यवस्था, आयात् पुनः पूर्ति योजना, राजकोषीय रियायतों इत्यादि) के स्थान पर विनिमय दर में परिवर्तनों द्वारा निर्यातों को प्रोत्साहित करना।

1980–81 के बाद से भारत को भुगतान शेष के क्षेत्रों में गंभीर समस्याओं को सामना करना पड़ां दूसरे तेल झटके ने भारत के आयात् व्यय में तेज वृद्धि कर दी परन्तु निर्यात् आय में बहुत कम वृद्वि कर दी परन्तु निर्यात् आय में बहृत कम वृद्धि हो पायी। इसके परिणामस्वारूप व्यापार शेष में घाटा बहुत बढ़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अदृश्य मदो से शुद्ध आय सातवीं योजना में होने वाले व्यापार घाटा के केवल 25 प्रतिशत की ही भरपाई कर सकी। 1990–91 के खाड़ी संकट से स्थिति और गंभीर हो गई। इस वर्ष 16934 करोड़ रूप्ये का व्यापार घाटा हुआ। इसके परिणामस्वरूप 1990–91 में चालू खाते में 17369 करोड़ रूपये का भारी घाटा हुआ । इतना ही नहीं 1980 के पूरे दशक में भारत की विदेशी वाणिज्यिक उधार तथा अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों पर निर्भरता लगातार बढ़ती गयी क्योंकि रियायती दरों पर प्राप्त विदेशी सहायता आवश्यकता से कहीं कम थी। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की विदेशी निवेशकों तथा उनकी अपेक्षाओं पर निर्भरता बढ़ गई। इस विवेचना से यह बात स्पष्ट होती है कि 1990 तथा 1991 की आर्थिक परिस्थितियों ने भारत को अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैक द्वारा थोपे गये संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाने के लिये विवश कर दिया भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैक के दबाव में आकर वैश्वीकरण की नीति अपनानी पड़ी।

उद्देश्य :

1. भारत में वैश्वीकरण अपनाने के कारणों का अध्ययन करना।
2. वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करना।
3. वैश्वीकरण का भारतीय उद्यमों मे प्रभाव का अध्ययन करना।
4. वैश्वीकरण को अपनाने की सुरक्षित सीमा का निर्धारण करना।

वैश्वीकरण का भारतीय उद्योगों पर प्रभाव :

वैश्वीकरण ने 'असमान प्रतिस्पर्धा' को जन्म दिया है। यह प्रतिस्पर्धा है शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगमों और कमजोर भारतीय उद्यमों के बीच। बस्तुतः भारत की बड़ी औद्योगिक इकाइयां भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में बहुत छोटी और बौनी है और उनमें से कुछ इकाइयों को तो

*प्राचार्य, श्री जमुना राम पी0जी0 कालेज चितबड़ागांव, बलिया, उ0प्र0

बहुतराष्ट्रीय कंपनियॉ हजम कर चुकी है और कुछ सांस रोककर अपने अस्तित्व के अन्त का इन्तजार कर रहीं है। जैसाकि पश्चिमी बंगाल के एक संसद सदस्य ने कहा है, भारत के वैश्वीकरण का अर्थ है हाथियों के झुंड में एक चूहे का घुसना।

1. भारतीय उद्यम अभी भी पहले के नियमों से जकड़े हुये है उदाहरण के लिये वे पुनः संरचना करके श्रमिकों को आसानी से निकाल नहीं सकते क्योंकि श्रमिक कानून इसकी इजाजत नहीं देते, इसके विपरीत बहुराष्ट्रीय निगम नए उद्यमों को बेहतर प्रौद्योगिकी और कम श्रम – शक्ति की सहायता से स्थापित कर रहें है।
2. कुछ क्षेत्रों में भारत सरकार की नीतियों में खुले रूप से बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ पक्षपात किया गया है। उन्हें करों में ऐसी छूटें दी गई है जो भारतीय उद्यमियों को उपलब्ध नहीं हैं।
3. देश में उत्पादित कई वस्तुओं पर अत्यधिक ऊंचे और बहुत स्तरों पर परोक्ष कर लगाये जाते है जबकि इन्ही वस्तुओं के आयतों पर इस प्रकार के कर नहीं है। इससे भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई पेश आती है।
4. भारतीय उद्यमों के लिये पूंजी की लागत बहुराष्ट्रीय निगमों की तुलना में बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि भारत ब्याज दरें दूसरे देशों में पाई जाने वाली व्याज दरों की तुलना में बहुत अधिक है।
5. अपनी अत्यधिक शक्तिशाली वित्तीय शक्ति के कारण, बहुराष्ट्रीय निगम न केवल भारतीय उद्यमों की तुलना में किसी उत्पादन क्षेत्र में अधिक लम्बे समय तक हानि बर्दाश्त कर सकते है। वे भारतीय उद्यमियों को उनके सहयोग से स्थापित उद्यमों में से आसानी से बाहर कर सकते है और उद्यमों पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर सकते है। वस्ततः जिस भारतीय उद्यम को चाहे तो खरीद सकते है।

सुझाव

वस्तुतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विश्व व्यापीकरण के दौर में भारतीय उद्यमकर्ताओं को भी सरकारी व्यवस्था द्वारा इस प्रकार का वातावरण, सुविधा व संरक्षण प्रदान करना होगा कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सामना कर सकें और प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. *Alok Ray (1993) – External sector Liberalisation in Indial" Economic and political weekly, Oct+ 2,p, 2161*
2. *Dalip s. swamy (1994) – The Political Economy of industrialization, New Delhi, PP 239-49.*
3. *Baldev Raj Mayyar (1998) – "Business and India's. Economic- Reforms" Economic and Political weekly, Sept 19.P. 2455*
4. *Government of India – Agricultural statistics at a Glance 2005 (New Delhi 245) Table 12.2*